(b) The Suppression of Unlawful Acts Against safety of Civil Aviation (Amendment Bill, 1993.

REPORTS OF THE PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

श्री एस. एस. अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) जनता क्लाथ स्कीम के संबंध में बहत्तरवां प्रतिवेदन ।

(2) 1991-92 के दौरान सरकारी क्षेत्र के चुनिंदा उद्यमों में सरकारी शेयरों के विनिवेश के संबंध में पचहत्तरवां प्रतिवेदन ।

MOTION FOR ELECTION TO THE COURT OF THE ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE (KUMARI SELJA) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I move :

> "That in pursuance of item (axxiv)' of clause (1) of Statute 14 of the Statutes of the Aligarh Muslim University, as amended by the Aligarh Muslim Usiversity (Amendment) Act, 1981 (62 of 19981), this House do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, one Member from among the Members of the House, to be a member of the Court of the Aligarh Muslim University."

The question was put and the motion was adopted.

(Ends)

REFERENCES

PROPOSED STRIKE BY POSTAL EMPLOYEES

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा) : धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष जी । मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहती हूं । आपको याद होगा कि कुछ माह पहले डाक विभाग के कर्मचारियों ने दशव्यापी हड़ताल की थी जिससे कि डाक विभाग का काम तो ठप्प हुआ ही था, आम जनता को भी काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा । आपको याद होगा कि वह हड़ताल काफी लम्बी खिंची थी और संसद के दोनों सदनों में उस हड़ताल की आवाज कई बार गूंजी थी । उसके बाद कुछ लोगों ने मध्यस्थता की और 10-12-1993 को विभाग और कर्मचारियों के बीच एक समझौता हो गया । मंत्रीजी के स्पष्ट आश्वासन के बाद उन कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापिस ली ।

उपसभाध्यक्ष जी, अब उन लोगों ने दोबारा से नोटिस दिया है । महोदय, 10-12-93 को उन्होंने हड़ताल वापिस ली और आज साढ़े चार महीने बीत गए हैं । महोदय, आपको याद होगा उस समय संसद के दोनों सदनों में मंत्रीजी स्वयं एक स्टेटमेन्ट लेकर आए थे, लेकिन आज 29 अप्रैल हो चुकी है और साढ़े चार महीने बीत जाने के बाद भी मंत्रीजी द्वारा दिए गए आश्वासनों के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है । उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया है । इसमें विशेष तौर पर जो सबसे बड़ी मांग एक्स्ट्रा डिपार्टमेन्टल एम्प्लाईज को लेकर थी, उनके बारे में कोई प्रगति नहीं हुई है । इन ई. डी. कर्मचारियों के बारे में एक कमीशन का गठन किया जाना था, लेकिन उसका गठन नहीं किया गया है । उनकी जो वित्तीय मांगें थीं, उनके संबंध में फायनेन्स मिनिस्ट्री की सहमति ली जानी थी, वह भी नहीं हुई है । इन ई. डी. कर्मचारियों ने कहा है कि कुछ मत कीजिए, केवल हमारी मांगों को आप पांचवे वेतन आयोग को दे दीजिए । वह भी नहीं हुआ है ।

और हालत यह हुई कि आज साढ़े चार महीने के बाद उन्हें दोबारा से संघर्ष का रास्ता अख्तियार करने पर मजबूर होना पड़ रहा है । महोदय, उनकी ज्वाइन्ट कांउसिल आफ एक्शन के द्वारा नोटिस दिया गया है जिसमें कि हर राजनीतिक दल से एफिलिएटिड यूनियंस हैं । एक बार डाक विभाग फिर